भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, चण्डीगढ़– बेज़ नम्बर 35–38, सैक्टर–4, पंचकुला ।
Project Implementation Unit, Chandigarh – Bays No. 35-38, Sector–4, Panchkula.
दूरभाष एवं फैक्स :– 0172–2587446, 2587447, ई–मेल :– chandigarh@nhai.org, piuchd@gmail.com

NHAI/PIU/CHD/11199/RO/ 993 Dated: 26th December, 2023

To

1 **M/s MSV International Inc.** (In association with MSPARK Futuristic & Associates), CHD-KHR–KRL #16-B, 2nd Floor, Surya Enclave, Kharar-Pb msv.kharar@gmail.com

2 **M/s MSV International Inc.** (in association witl P.K Engineers Pvt. Ltd.), H.N. 280, Giani Zail Singh Nagar, Ropar-140001(Kur-Kir)

3 **M/s G-Eng Advisory Services Pvt. Ltd** (JV) M/s Voyants Solutions Pvt. Ltd. and In association with NU-infra Engineering P. Ltd. (Mohali Sirhind), 86-B, Daizy Tower, Bollywood Green City, Sector-113, Mohali

4 **M/s Upham International Corporation in JV** with M/s SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. (LDH-RPR-III) Ward No. 1, A-1 Colony, Singhpura Road, Kurali, District SAS Nagar-140103 (Pb.)

5 **M/s MSV International Inc.** in association with M/s Mahamarg Infra Consultant Pvt. Ltd. (Z-Sang) 7485, First Floor, Block-H, Aerocity Mohali, Punjab-140306 msv.sangrur@gmail.com

6 **M/s Voyants Solutions Pvt. Ltd.** (IT CITY) In JV M/s G-Eng Advisory Services Pvt.Ltd. 40/1, Princy Villa, Sector – 125 , Sunny Enclave, Kharar, Sahibzada Ajit Singh Nagar-140301 (Pb.)

7 **M/s Aecom Asia Pvt. Ltd.** #352, Patel Nagar, Near Vaishno Mata Mandir Bibi Wala Chownk, Bathinda-151001 (Pb.) aecombti@gmail.com

8 **M/s L N Malviya Infra Projects Pvt. Ltd.** *(in association with Intratech Civil Solutions & Consultant)* Mata Kaushalya Niwas, Chahal Colony, Street No -3, Near Nankana Chowk, Opposite Kt Royal Hotel, Sangrur-148001sangrurbypass07@gmail.com

Sub: **Delayed or Non-Payment of Staff Salary**

Ref.: Complaint addressed to the Hon'ble Minister Road Transport & Highways

Sir,

Please find enclosed herewith a complaint addressed to the Hon'ble Minister Road Transport & Highways has also been received in this office recently alleging non-payment of the salary to workers engaged ranging from 5 – 8 months resulting in great financial hardship. This has been viewed very seriously being sheer and willful contravention of contract provisions and applicable laws, which undoubtedly undermines the dedication of the staff deployed for the project work, which is bound to suffer due to the financial crunch besides affecting the project work despite the fact that this office is releasing the payments promptly for the bills submitted in this office. Such complaints casts aspersion on the working of NHAI, which in no case is acceptable to the Authority.

2. In view of above, it is requested to bestow special attention to this aspect and ensure that payment of salaries to the staff / workers deployed for the project work is released in time. It

-d-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, चण्डीगढ़– बेज़ नम्बर 35–38, सैक्टर–4, पंचकुला ।
Project Implementation Unit, Chandigarh – Bays No. 35-38, Sector–4, Panchkula.
दूरभाष एवं फैक्स :– 0172–2587446, 2587447, ई–मेल :– chandigarh@nhai.org, piuchd@gmail.com

is equally important to submit a certificate stating that the payment of salary / wages have been released to the staff / workmen deployed (duly supported by bank statement), while submitting the invoice preferring payment.

3. This is issued for strict compliance.

Yours faithfully
26/12/23

Encl.: As above

(Pardeep Atri)
GM(T)-cum-Project Director
NHAI, PIU Chandigarh

-d-

सेवा में

माननीय श्री नितिन गडगरी जी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :- कन्सल्टेन्सी में कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में अवगत करवाने हेतु।

श्रीमान जी

हम आपका ध्यान है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन आने वाली कंसल्टेंट कम्पनी में हो रही बहुत सारी गड़बड़ियों की और दिलाना चाहते है। आजकल बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंसल्टेंट कम्पनी खुल गयी है। जो की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट तो उठा रही हैं लेकिन फिर ढंग से उनको चला नहीं पा रही हैं और उसके बाद अपने कर्मचारीओं का बहुत जायदा शोषण कर रही है ! आपको जानकार यह हैरानी होगी की ये अपने कर्मचारियों को ५ से ७ वेतन तक नही दे रही है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीयों के साथ मिलकर अपने सारे बिल निकलवा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी इनके सारे बिल साथ के साथ क्लियर कर रहे है बिना जांचे परखे की यह कंसल्टेंट कम्पनी आगे अपने ,कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं की नहीं और यह यही सबसे बड़ा जांच का विषय है। और यह सब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन आने वाले PIU और रीजनल ऑफिसेस के साथ मिलकर कर रहे है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और उसके अधीन आने वाली PIU 's में दिक्कत ज्यादा है ! इसे से पहले भी बहुत बार शिकयत की गयी लेकिन कोई हल नहीं निकला ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लाभ देने के लिए बिल को क्लियर कर रहे हैं बिना जांचे परखे की की कंसल्टेंट कम्पनी आगे अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है की नहीं। श्रीमान जी आप एक महीने के वेतन में कर्मचारी ५ से ७ महीने कैसे निकलेगा ! लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना दिया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारयों ने की की कंसल्टेंट कम्पनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सोचते है वो सबसे ऊपर है सरकार से भी और सिस्टम से भी ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारी इस मामले में बिलकुल अनजान बन कर बैठे हुए है। यह धांधली हरजगह हो हो रही हैं १०-१२ हज़ार कमाने वाला कर्मचारी कैसे गुज़ारा करेगा।वो अपना परिवार कैसे पालेगा। सर सारे कर्मचारी बहुत बहुत दूर से नौकरी करने आये हैं और किराये के घरों में रहते है उनको रूम किराया बिजली का खाने के और परिवार की भी जिम्मेदारियों हैं तो बिना वेतन के ४ से ६ महीने बिना वेतन के कैसे गुज़ारा करेंगे। जैसे कंसल्टेंट कम्पनी के और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वालो के परिवार हैं वैसे ही कर्मचारिओं के भी परिवार है। क्या यह कंपनी वाले १ महीने से पेमेंट से ६ महीने का खर्चा निकाल सकते हैं ?नहीं तो फिर कर्मचारी कैसे गुज़ारा करें !

सबसे बड़ी विडंबना यह है की न यह कंपनियां PF और ESI जैसी मुलभूत सुविधाएं भी नहीं देती अपने कर्मचारियों को जो की सरकार की जरूरी योजनाएं हैं और कंपनी को देना जरूरी है ! कंसल्टेंट कंपनियां खुद का पैसा बचाने के चकर में मुलभूत सुविधाएं भी नहीं नहीं देती है ! ये सरासर कंपनियां की मनमानी हैं ! कर्मचारियों के हितों का शोसन हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारयों को बहुत बार शिकायत की गयी लकिन कोई हल नहीं निकला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी सिर्फ कंपनियों के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं ! श्रीमान जी हम आपका ध्यान एक और बात की और दिलाना चाहते हैं की कर्मचारियों को ये बहुत ही काम वेतन देते हैं ! और भी ४ इ ६ महीने के बाद बिना ESI और PF के अगर कोई कर्मचारी भी सैलरी मांगता तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका ५ से ८ महीने का वेतन

तक भी नहीं दिया जाता है इतना बुरा हाल है इन कम्पनियो का ! और सब से जायद इस बात का दुःख है की जो सरकार द्वारा निर्धारित कानून है मिनिमम सैलरी का वो तक नहीं दे रहे है ना ही कर्मचारियों को किसी प्रकार की छुट्टी का कोई प्रावधान है ! सर जो भी कम्मापनियों बिल जमा करवाती हैं उनमें बहुत सारी कमियांहोती हैं फिर भी इनके बिल क्लियर हो जाते है वो भी २ से ३ दिन में बिना किसी प्रॉब्लम के कमाल की बात है यह ! कम्पनिओं के ऑफिसेस मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी उन कम्पनिओं को करोड़ों के प्रोजेक्ट दे देती है जिन कंपनियों के पास एक महीने तक का वेतन देने का पैसा नहीं होता है और यह छोटे छोटी कम्पनिया कर्मचारियों के वेतन रोक कर उन पैसे से प्रोजेक्ट उठा रही हैं और कर्मचारी और उनके परिवार वालों के भूखे मरने तक की नौबत आ गयी है ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी इस बारे में सोचना होगा! सर हमें यह बताते हुए बहुत दुःख हो रहा है की यह कंपनियों का इतना बुरा हाल है की ईद हो होली हो दिवाली हो रक्षाबंधन हो किसी भी फेस्टिवल पर बेत्तन नहीं देती है इनकी सोच ऐसी है की सिर्फ हमें और हमारे परिवार की ही पैसे की जरूरत है बाकी जो कर्मचारी इन्होने जॉब पर रखे है उनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं हैं वो मर भी जाएँ पर यह उनको वेतन नहीं देंगे ! सर ये प्राइवेट कम्पनिओं वाले इतने जयादा बेशर्म और ढीठ हो चुके हैं की कर्मचारी वेतन के लिए कितनी बार भी रिक्वेस्ट कर लें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है! सबसे जायदा दुःख की बात यह है की हर कर्मचारी इनसे तंग हो चूका है कोई भी कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है ! वेतन भी भीख की तरह माँगा जा रहा है! इनको सिर्फ प्रोजेक्ट्स और अपने परिवार की फ़िक्र है और जो सेकड़ो कर्मचारी काम कर रहे है इनको कोई मतलब नहीं है ! बहुत ही ज्यादा मानसिक शोषण किया जा रहा है ! इतने महीने तक किसी का वेतन नहीं देंगे तो वो कैसे गुज़ारा करेंगे उनके भी परिवार है जैसे कम्पनिओं वालो के हैं !

सर अगर आप पिछले सिर्फ एक साल का रिकॉर्ड यह चेक करवा लें की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन कम्पनियों के बिल कब कब क्लियर किये और उन बिल से कर्मचारयों को कब कब वेतन दिया तो सब कुछ क्लियर ह जाएगा हमें नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

<u>सर हम लोग यही चाहते की किसी भी नयी कंपनी को प्रोजेक्ट देने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए</u>

1. हर ६ महीन के बाद सारी कम्पनिओं का निरिक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (हेड क्वार्टर दिल्ली) के दवारा किया जाए! क्यूंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोकल अधिकारी कंपनियों के साथ मिलते हुए होते हैं वो सही रिपोर्ट नहीं देते है !

2. जो भी कंपनियों अपने कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं देती हैं उनके खिलाफ कठोर करवाई की जाए!

3. हर कंसल्टेंट कंपनी के लिए यह सुनिश्चित किया जाये की वो १० तारीख तक वेतन दे देगी नहीं तो उसका बिल क्लियर नहीं होगा और अगर कोई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लोकल ऑफिस (PIU) बिल क्लियर करता हैं तो उनके खिलाफ भी करवाई की जाए !

4. हर कर्मचारी का EPF और ESI काटना जरूरी किया जाए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसको मॉनिटर करेगा ताकि आने वाले टाइम में कर्मचारी और उसके परिवार को कोई दिक्कत न हो वो भी सम्मान के साथ जी सकें !

5. और जो भी कंपनी ऐसा न करें उनको ब्लेकलिस्ट कर दिया जाए क्यूंकि सरकार की योजनाओं पर हर कर्मचारी का हक़ है कम्पनियां उसको देने से मना नहीं कर सकती हैं।

6. हर कर्मचारी कों त्यौहार से पहले वेतन दे दिया जाए ताकि वो भी खुशी खुशी त्यौहार मना सकें।

7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीयों को निर्देश दिया जाए की समय समय पे इस बात का ध्यान रखा जाए की कंसल्टैंसी कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय न हो क्यूंकि उनका वेतन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही देता है।

8. कंसल्टेंसी कर्मचारयों के लिए कंप्लेंट सेल बने और उनको मूलभूत सुबिधायें दी जाएँ जो उनका हक़ हैं कोई कर्मचारी अगर कंपनी सेअलग होता हैं तो उसको पूरा वेतन टाइम से दिया जाए अगर कमपनी ऐसा न करे तो कठोर करवाई की जाए ! सरकार जो भी समय समय पर नियम बनाये या जो नियम अभी लागू हैं कम्पनिओं उनको माने ।

9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी कंसल्टैंट कम्पनियों के लिए काम बंद करके देश के लिए काम करें।

10. जब भी कोई कंपनी एग्रीमेंट करे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तो यह भी मेंशन किया जाए की उनको टाइम से वेतन देना है कर्मचारियों को और छुट्टी का भी प्राबधान होना चाइये एग्रीमेंट में क्यूंकि कंपनियां उसका हवाला देकर बच निकल जाती हैं की एग्रीमेंट में नहीं है ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए !

11. मिनिमम सैलरी जो भी राज्य सरकार दवारा ये केंद्र सरकार दवारा निर्धारित की गयी हैं वो हर कर्मचारी को मिले।

12. कर्मचारी काम में भी १०० प्रतिशत तभी दे पाएंगे जब उनका वेतन टाइम से आएगा और उनको सरकार दवारा निर्धारित वेतन मिलेगा नहीं कर्मचारी ढंग से काम ही नहीं करेंगे जिस से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इमेज ख़राब होगी और लोंगो को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी।

13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट्स की मॉन्टिनेरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया है हर प्रोजेक्ट वाइज पर बिंडवना यह है की पोर्टल में सब जानकारी तो हैं पर कंसल्टैंसी में कितने कर्मचारी है उनका कंपनी कितना क्लेम करती है और कर्मचारी को कितना देती है महीना दर महीना वेतन देती है या नहीं कर्मचारियों को ESI और PF मिलता है की नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है कृपा पोर्टल में वो भी अपडेट करवाने की कृपा करें।

14. जो भी सर हमने परेशानिया लिखी है वो सब सही है। हम अपना नाम और पता नहीं लिख सकते है नहीं तो पता नहीं ये कंपनी वाले हमारे साथ क्या सलूक करेंगे ! हम सिर्फ अपना हक़ मांग रहे हैं ! तो आपसे हाथ जोड़कर बिनती है की कम से कम एक बार जरूर चेक करवाएं ताकि सचाई का पता चल सके !

यह आपसे आपसे अनुरोध और उम्मीद है की आप कर्मचारियों की जो भी ऊपर लिखित समस्याएं हैं उनके बारे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीयों को उचित निर्देश देंगे और कर्मचारयों की की इन समस्याएं को जल्दी से जल्दी हल करवाने की कोशिश करेंगे आपकी बहुत कृपा होगी !

धन्यबाद सहित !

प्रार्थी
सारे पीड़ित कर्मचारी

इसकी एक प्रति निम्लिखित की सेवा में सुचंनार्थ एवम आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित है !

1. श्री संतोष यादव (अध्यक्ष) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नई दिल्ली
2. श्री नीरज कुमार चीफ विजिलेंस अफसर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नई दिल्ली
3. श्रीमती नीलम शमी राव (आईएएस) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली
4. डॉक्टर राजेंदर कुमार (आईएएस), महानिदेशक- कर्मचारी राज्य बीमा निगम। नई दिल्ली
5. श्री रेमिस तिरु मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) - नई दिल्ली